

Obligation Conditions as stipulated in the Foreign Collaboration Approval, (b) During the last 3 years, 38 companies were found to be defaulting on Export Obligation Conditions imposed on their respective Foreign Collaboration Approvals. The list of such companies is annexed as statement. (*See below*)

(c) These cases are under adjudication for imposition of fiscal penalties as per terms and conditions of the Legal Undertakings filed by the Companies.

Statement

List of Companies

SI. No.	Name of the firm
1.	M/s Eastern Chemofarb Ltd,
2.	M/s Kirlosekar Pneumatics Co.
3.	M/s Bayrian Shoes Ltd,
4.	M/s Sreenivas Engg. Co.
5.	M/s Zenith Steel Pipes & Inds. Ltd,
6.	M/s Concast India (P) Ltd,
7.	M/s Nucon India (P) Ltd,
8.	M/s Indo-Nippon (P) Ltd,
9.	M/s Hindustan Dorr-Oliver Ltd,
10.	M/s Surimal Rajan Guha,
11.	M/s Exports India Ltd,
12.	M/s I.A.E.C. (Bombay) Ltd,
13.	M/s East Coast Pesticides,
14.	M/s Indian Furnance Co,
15.	M/s Leisure Land (P) Ltd,
16.	M/s New Standard Engg, Co. Ltd,
17.	M/s Sonnex-flex Abrassiv Ltd,
18.	M/s Chandan Engg. Inds. (P)
19.	M/s Harish Chandra Jain,
20.	M/s Vijay Industries,
21.	M/s Biax Packaging Ltd,
22.	M/s TVS Electronics (P) Ltd,
23.	M/s National Peroxide Ltd,
24.	M/s Food & Specialisations Ltd,
25.	M/s Sumac Engg.,

SI. No.	Name of the firm
26.	M/s Marshal Sons & Co.,
27.	M/s Indo-Foreign Chem.,
28.	M/s Bharat Linders (P) Ltd,
29.	M/s Arnold-Hamiman.
30.	M/s New Standard Engg. Co.,
31.	M/s Associated Cement Ltd,
32.	M/s Perfect Fasteners (P) Ltd,
33.	M/s G.E.C.
34.	M/s Bio. Con. India Ltd,
35.	M/s Microwave Products (I) Ltd,
36.	M/s Leather Crafts (1) Pvt. L<d,
37.	M/s Greaves Cotton Ltd,
38.	M/s Indian Splicing (Mech.) Accessories Ltd., (Usha Engg.)

Programme launched by UNIDO

2730. SHRI SOLIPETA RAMACHANDRA REDDY: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) the details of the new programmes launched by United Nations' Industrial Development Organisation to promote foreign investment in India termed as Investment and Technology Promotion Initiative; and

(b) in what manner it will help small and medium enterprises to locate the right partner for investment and joint ventures?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI MURASOLI MARAN): (a) and (b) With the assistance of Ministry of Industry, Government of India, United Nations Industrial Development Organisation (UNIDO) has recently launched a new programme called "Investment & Technology Promotion Initiative" (ITPI). Under this programme, a separate ITPI Office will be set up at New Delhi under the supervision of UNIDO Country Director to undertake certain activities with

a view to achieving the following objectives:—

1. Assisting entrepreneurs to identify joint venture and technology partners from other countries.
2. Networking of focal points throughout India of public and private sector institutions, active in promotion of business cooperation between Indian firms and foreign firms.
3. Increasing the awareness of services available from UNIDO and its investment promotion services in developed and developing countries in the area of investment project identification, formulation, screening and evaluation.
4. Organising INTECHMARTs for technology and investment match-making at the State-level.
5. Following up the projects identified for joint venture in the previous INTECHMARTs held at New Delhi in 1995 and 1996.

The Project is for a period of two years starting from 1st May, 1996. The ITPI Project is mainly to promote cooperation between small and medium enterprises for technology transfer and joint ventures. This will contribute to small and medium enterprises development, which in turn will lead to skills upgradation and employment generation having, thus, di-ret impact on poverty alleviation programme.

अनुसूचित जनजातियों का वित्तुप होना

2731. श्री जगन्नाथ सिंह: क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या अनुसूचित जनजातियों के अंतर्गत आने वाली जातियों में से कुछ जातियाँ वित्तुप हो रही हैं; और
- (ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है?

कल्याण मंत्री (श्री बलराम सिंह रामुवासिनिया):

- (क) जी, नहीं।
- (ख) प्रश्न नहीं उठता।

गुजरात हेतु कोयले की मांग और आपूर्ति

2732. श्री अनन्तराव देवशंकर शिंदे: क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात सरकार को इसके विभिन्न क्षेत्रों के लिए कोयले की प्रतिवर्ष कितनी मात्रा की आवश्यकता है और इसका जिले-वार ब्यौर क्या है;

(ख) क्या इसकी मांग और आपूर्ति में बड़ा फाँट अंतर है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौर क्या है; और

(घ) गुजरात को कोयले की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह): (क) से (घ) कोयले की आवश्यकताओं का समय-समय पर के लिए उद्योगवार/क्षेत्रवार मूल्यांकन किया जाता है। इनका मूल्यांकन राज्यवार अथवा जिलावार नहीं किया जाता है। किंतु कोयला कंपनियों द्वारा सभी उपभोक्ताओं को कोयले की आपूर्ति की व्यवस्था उन्हें दिए गए संयोजनों/प्रयोजनों तथा उपभोक्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए कार्यक्रम के अनुसार की जाती है। उच्चतम प्राथमिकता के परिणामस्वरूप, जो कि विद्युत क्षेत्र को कोयले की आपूर्ति के मामले में दी जाती है, और कोयले की मांग में इस क्षेत्र से तेजी से वृद्धि होने के परिणामस्वरूप औद्योगिक उपभोक्ताओं को कोयले की आपूर्ति प्रभावित हुई है। विद्युत क्षेत्र के अलावा, उपभोक्ताओं को भी कई कुल आपूर्ति, जिसमें गुजरात की औद्योगिक तथा एस-एस-आई-यू यूनिटें शामिल हैं, वर्ष 1995-96 में 25.76 लाख टन (अंतिम) की आपूर्ति की गई, जबकि 1994-95 में यह 32.16 लाख टन (अंतिम) थी। किंतु गुजरात के विद्युत क्षेत्र को दिया गया कुल प्रेषण में 125.84 लाख टन (अंतिम) तक की वृद्धि हो गई, जबकि 1994-95 में प्रेषण 118.88 लाख टन (अंतिम) था।

कोयला कंपनियाँ देश में सभी उपभोक्ताओं को कोयले की आवश्यकताओं को पूरा करने का कोयले का उत्पादन करके प्रयास कर रही हैं, जिसमें गुजरात के उपभोक्ता भी शामिल हैं। इसके अलावा, कई कोलियरियों से उदारीकृत विक्रय योजना के अंतर्गत कोयले की पेशकश भी की जा रही है, इस योजना के अंतर्गत कोयले की आपूर्ति बिना संयोजनों/प्रयोजनों की